2 राष्ट्रीय सहारा
www.samaylive.com
पटना ● बृहस्पतिवार ● 9 मई ● 2013

खेती को हर हाल में मिलेगी बिजली

पटना (एसएनबी)। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि घर को बिजली मिले या न मिले पर खेती के लिए जरूर मिलेगी। दूसरी हरित क्रांति बिहार से ही होगी। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि कार्य के लिए बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार वादा और इरादा को लेकर कार्य कर रही है। बिजली के क्षेत्र में 2015 तक हमारी स्थिति काफी अच्छी और 2020 में सरप्लस बिजली हो जायेगी।

▶ पावरिंग बिहार पर आयोजित सेमिनार में ऊर्जा मंत्री ने दिलाया बिजली के मामले में बेहतरी लाने का भरोसा

श्री यादव बुधवार को पावरिंग बिहार पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निजी कंपनियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार मुनाफा नहीं कमाती है। हमारा कार्य जनता को सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध कराना है। बिहार में शहरी आबादी मात्र 11 फीसदी है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करते हैं। इस कारण बिजली की बर्बादी भी होती है। उन्होंने कहा कि नयी तकनीक आज की आवश्यकता है। परंतु वास्तविकता को देखना होगा। बिहार में बिजली की मांग व्यापक स्तर पर बढ़ी है। पटना में 440 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। बिहार में 1977 के बाद बिजली के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद भी सभी आंकड़ों में बताया जाता है कि बिहार काफी पीछे है।

सेमिनार : बिजली की स्थिति और इसकी बेहतरी के उपायों पर विमर्श में शामिल ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव व अन्य।

आपलोग वास्तविकता भी बतायें। उन्होंने कहा कि राज्य में आठ पावर ग्रिड बनकर तैयार हो गये हैं। बिजली की स्थिति में सुधार के लिए 16 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार विभिन्न बैंकों से कर्ज लेकर सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शत-प्रतिशत बिजली खरीदते हैं। इस कारण घाटा ज्यादा है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पांच कंपनियों में बांटा गया है। अब घाटा कम होगा। उन्होंने कहा कि हर छह महीने में आपलोगों को बिजली की स्थिति में सुधार दिखेगी। ऊर्जा विभाग के सचिव संदीप पौंडरीक ने कहा कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 35 लाख है। इन सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। जून तक सभी उपभोक्ताओं के घर में मीटर लगा दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उत्पादन और वितरण हमारी पूर्ण समस्या है।

▶ जून तक सूबे के सभी 35 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगा दिया जायेगा बिजली का मीटर : पौंडरीक

उन्होंने कहा कि दो वर्षों के बाद बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार दिखेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष यूएन पंजियार ने कहा कि पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में वितरण की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अनुदान पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने वित्तीय वर्ष 2013-14 में टैरिफ बढ़ाया है। उपभोक्ता बिल का भुगतान प्रत्येक महीने करें इसकी कोशिश की जा रही है। सेमिनार को टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने भी संबोधित किया। संचालन सीआईआई, बिहार के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुभाष सेठी ने।